



विस्तृत खबरों के लिए **QR**
कोड स्कैन करें।
मुफ्त पढ़ें **E-paper**

हल्लुवानी, मंगलवार 16 सितम्बर 2025 हल्लुवानी संस्करण: वर्ष 23 अंक 21 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00

नई दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून, हल्द्वानी, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ व लखनऊ से प्रकाशित



समय से 3 दिन पहले पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर, नागौर, जोधपुर और बीकानेर से मानसून विदा ले चुका है। अगले दो-तीन दिन में पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों से भी मानसून लौटना शुरू हो जाएगा। जबकि मध्य प्रदेश में मानसून दो हफ्ते और रहेगा। देश के अधिकांश हिस्सों से 15 अक्टूबर तक मानसून पूरी तरह लौट जाएगा। दक्षिण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में बारिश जल्दी रह सकती है।

संतुलित फैसला

समवार को मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति आंगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने वक्फ सशोधन अधिनियम 2025 पर अपने अंतरिम फैसले में पूरी तरह रोक लगाने से इन्कार कर दिया, लेकिन साथ ही कहा कि अंतिम निर्णय आने तक कुछ प्रावधानों पर रोक रहेगी। पीठ ने यह भी कहा कि अदालतों को संसद द्वारा बनाए गए कानून की वैधता माननी चाहिए और केवल दुर्लभतम मामलों में ही स्थगन देना चाहिए। 22ई और को अदालत ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं (जिनकी संख्या सी से अधिक है) के एक समूह पर अंतरिम रोक लगाने के अनुरोध पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने इन याचिकाओं पर गहनता से विचार किया और पाया कि कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता, लेकिन पीठ ने यह भी माना कि कुछ धाराओं को कुछ संरक्षण की आवश्यकता है। जैसे पीठ ने कहा कि कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों का न्याय निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने साफ कहा कि अगर ऐसा होता है तो शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होगा। ठीक इसी तरह पीठ का यह भी कहना था कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में क्रमशः 22 और 11 सदस्यों में से तीन से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए। हालांकि ऐसा कहते हुए यह भी साफ किया कि यह न्यायालय कोई निर्देश जारी नहीं कर रहा है। फिर भी उचित यही होगा कि पीठ ने पांच साल तक इस्लाम का पालन के मानदंड के कार्यान्वयन पर भी रोक लगा दी। ऐसा करते हुए पीठ का कहना था कि जब तक नियम नहीं बन जाते तब तक वक्फ संपत्ति घोषित होने से पहले इस पर रोक रहेगी। पीठ का मानना है कि बिना किसी तंत्र के यह मनमाने शक्ति के प्रयोग को बढ़ावा देगा। अब अंतराल तबवरी तो तभी साफ होगी जब पीठ का संपूर्ण फैसला आएगा, लेकिन फिलहाल आए फैसले से सभी पक्ष संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। जहां केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उच्चतम न्यायालय के वक्फ अधिनियम 2025 पर आए निर्णय का स्वागत किया है और इस निर्णय को लोकतंत्र के हित में बताया है वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारी समि. के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी पीठ के फैसले की सराहना की है और कहा है कि वे उच्चतम न्यायालय द्वारा मुस्लिम पक्ष की दलीलों को स्वीकार करने के आदेश का स्वागत करते हैं और उम्मीद जताई कि इस मामले पर पूरा फैसला आने पर मुसलमानों को पूर्ण राहत हासिल होगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमें उम्मीद थी कि पूरे एकट पर स्टे लिया जाएगा, लेकिन कुछ अहम बातों पर स्टे लिया गया, जिसका वह स्वागत करते हैं। उनके अनुसार अभी पूरा फैसला आना बाकी है, उम्मीद करते हैं कि हम रिलीव हासिल होगी। निश्चित रूप से कोर्ट को जो अंतरिम फैसला आया है वह बेहद संतुलित है और तर्कसंगत भी है, जबकि सरकार की भाषा से लुहा है कि वह फैसले से इतनी खुश नहीं है और वह यही दुहाई दे रही है कि संसद के पास कानूनों में अदालतों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

...तो सिख कैसा महसूस करेंगे

वक्फ संशोधन अभिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम आदेश है, हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र कोर्ट इस पर कानून पर जल्द अंतिम फैसला सुनाए और सुनवाई शुरू हो, सीओ को नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह व्यक्ति जहाँ तक संभव हो मुस्लिम होना चाहिए, अब सरकार यही कह रही कि उन्हें कोई योग्य मुस्लिम नहीं मिला, जो पाठों किसी मुसलमान को सांसद का डिकेट नहीं देती, जिसके पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, क्या वह मुसलमान अधिकारी चुनेंगे? खुफिया विभाग में कितने मुसलमान अधिकारी हैं, वे वक्फ में चले मुसलमानों को नियुक्ति करेंगे, यह संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) में किसी गैर-सिख को सदस्य बना दिया जाए तो सिख कैसे सहमत करेंगे।

—असदुद्दीन ओवैसी, प्रमुख, एआईएमआईएम



ने पाल के अंतरिम सरकार की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री सुशीला कार्का ने पदभार ग्रहण करने के बाद मातहतों के साथ संक्षिप्त बातचीत में साफ कर दिया है कि वे सत्ता का स्वाद चखने नहीं आई हैं। वह महीने बाद होने वाले चुनाव के बाद वे नए प्रतिनिधि सभा को सत्ता की चाभी सौंप देंगी। हां इस दौरान उनकी पूरी कोशिश होगी कि नेपाल अब सत्ता के लिए और ईमानदार सरकार के युवाओं को। इसके साथ संघर्षशील व ईमानदार युवाओं को आगे आना होगा।

उन्होंने जो दूसरी बड़ी बात कही वह नेपाल को तहस-नहस करने वालों की शिनाख कर उन्हें सजा-दिलाने का। सुशीला कार्की के लिए यह बड़ी चुनौती है, क्योंकि आंदोलन तो जेन जी के हाथ में था और उन्होंने को सहमत से वह प्रधानमंत्री बनी हैं तो क्या जेन जी के आंदोलन में दूसरे लोग भी घुस आए और देखते देखते नेपाल को लोख में तब्दील कर दिया? ये दूसरे लोग आखिर कौन हो सकते हैं? इसे लेकर कायसबाजी का दौर जारी है। हर जुबान पर अलग-अलग चर्चाएँ हैं। अब अगर जेन जी के आंदोलन में भारी संख्या में उपद्रवी घुस आए और काठमांडू से लेकर नेपाल के मैदानी इलाकों तक आंदोलन को हिंसात्मक बना दालें तो यह मानना होगा कि वे कितने मुस्तैद थे? प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के नेतृत्व का मौजूदा प्रशासन इन उपद्रवियों की शिनाख कैसे और किस आधार पर करता है यह देखने वाली बात होगी। भारी हिंसा के बीच पदासीन हुई सुशीला कार्की के समक्ष सिर्फ यही चुनौती नहीं है, देखें तो उनके समक्ष चुनौतियाँ काँ पहाड़ें और टूटे फूटे नेपाल को नया जीवन दे पाने में कामयाब होंगी। सुशीला कार्की न्याय विद् के साथ एक राजनीतिस्त परिवार से जुड़े रहने के नाते वे परिचयव राजनीतिस्त भी हैं। इसकी झलक तब देखने को मिली जब जेन जी के तरफ से उनका नाम फाइनल होवें के बाद भी वह प्रधानमंत्री बनने को लेकर हड़बड़ी में नहीं दिखीं। प्रधानमंत्री पद की शायश उन्होंने तभी ली जब राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल को संसद विघटन की उनकी मांग को मानना पड़ा। सुशीला कार्की के इस बात की सभी कायल हुए तो फिर पुराने प्रतिनिधि सभा का ही नेतृत्व करना है तो प्रष्ट्यकार जिसके खिलाफ इतना बड़ा आन्दोलन हुआ, उससे पर पापा संभव नहीं है। उन्होंने दो टुक करवा कि वह एक प्रष्ट सरकार का नेतृत्व नहीं करना चाहेंगी।

सुशीला कार्की के पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी का ताल्लुक नेपाली कांग्रेस से थे जिन्हें स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला का नजदीकी माना जाता है। दुर्गा प्रसाद सुवेदी पर 1973 में रायल नेपाल के जहाज

भविष्य में ऐसे विद्रोह की पुनरावृत्ति को रोकने और शासन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए स्वतंत्र एंटी कर्षण कमीशन बनाना जाए जो राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हो। साथ ही करेट नेताओं पर मुकदमे चलाए जाएं। रोजगार सृजन हेतु युवा केंद्रित नीतियां –आईटी हब, कृषि सुधार अपनाए जाएं। एमसीसी ग्रांट को पारदर्शी तरीके से उपयोग में लाया जाए। साथ ही राजनीतिक स्थिरता हेतु चुनाव सुधार और राजनीति में युवाओं को शामिल किया जाए। इस समय नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय सहायता की नितांत आवश्यकता है।

नेपाल: सुशीला कार्की के समक्ष चुनौतियों का पहाड़



के अपहरण का भी इल्जाम है। हालांकि यह एक आंदोलन का हिस्सा थे। इस घटना पर उनको एक पुस्तक की खूब चर्चा रही। बहरहाल सुशीला कार्की के पति का नेपाली कांग्रेस से ताल्लुक होने का कोई छाप इन पर नहीं है और न ही नेपाली जहाज के अपहरण से ही उनका कोई लेना देना रहा। वह तब भी अपनी मर्जी की मुछ्ता रही और आज भी। बतौर न्यायाधीश उनके कई फैसले चर्चा में रहे जिसमें नेपाली कांग्रेस के एक मुस्लिम नेता के खिलाफ फैसला राजनीतिक गतिार्यों में भूचाल जैसा था। उनको जो कार्यशैली और दृढ़ इच्छाशक्ति है निःसंदेह नेपाल को उसका फायदा मिलेगा। यद्यपि कि समय कम है, छह महीने बाद होने वाले चुनाव का परिदृश्य क्या होगा, इस पर कुछ भी कयासबाजी ठीक नहीं है। आगामी चुनाव को लेकर भारत विरोधी और भ्रष्टचम सरकार का नेतृत्व करने वाले कई शर्मा आंली को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाले जेन जो के नीजवानों का खूब भी स्पष्ट नहीं है। वह अलग कोई राजनीतिक दल गठित करेगा या मौजूदा किसी दल के साथ आधुरी, यह भी तय नहीं है। भविष्य के नेपाल में साफ-सुथरी सरकार के लिए उन युवाओं का राजनीतिकरण जरूरी है। बेहद कम समय में सुशीला कार्की के समक्ष नेपाल को फिर से सजाने संवारने की चुनौती भी है। आगजनी और तोड़फोड़ में नेपाल को अरबों-खरबों का नुकसान हुआ है। नेपाल को फिर से बनाने में इतनी बड़ी रकम जुटाना आसान नहीं है। इसके लिए कोन-कोन देश अगर आता है, यह काफी कुछ उन सरकार के विदेश नीति पर निर्भर करेगा। दूरिस्ट जो नेपाल के आर्थिक स्रोत का बड़ा जरिया है, उसे

स्थापित करना भी बड़ी चुनौती है। नेपाल यूँ तो आंदोलनों का देश है। सबसे भयावह आंदोलन लोक कर्तव्य बहाली को लेकर था, जिसे जनयुद्ध के नाम पर सै भी जाना जाता है, उसमें जनहानि खूब हुई लेकिन सरकारी इमारतों को क्षति नहीं पहुँचाई गई थी। बीच बीच में और भी तमाम आंदोलन हुए लेकिन वे इतना भयाक्रांत नहीं रहे। इस बार के आंदोलन की भयावहता देख भारत सहित अन्य देशों के दूरस्थों का रुख नेपाल की ओर होने में वक़्त लगेगा। काठमांडू में भारतीय पत्रकारों को चुन-चुन कर मारा गया यह जानते हुए कि जले धुने नेपाल के पुनर्निर्माण में भारत ही मुख्य सहायक होगा। दरअसल यह सब भारत के प्रति ओली सरकार द्वारा बोए गए जहर का ही असर था। कुछ वर्ष पूर्व आए भूकंप से नेपाल में जितनी तबाही नहीं हुई थी, नेपाली युवाओं ने अपने हाथों से नेपाल को उससे बड़ी त्रासदी दे दी। जितनी किन्मथी थी, उसे हटाने के लिए आंदोलन ठीक था, लेकिन सरकारी संपत्तियों को सुपुर्द-ए-खाक करना नादानी थी। काठमांडू से लेकर नेपाल के तमाम शहरों कस्बों में जलते हुए मकान, सरकारी इमारतों को देख ऐसा लगता है कि इसका पुनर्निर्माण आसान नहीं है। हर जुवान पर चर्चा है कि अब परंप्रतिनाथ ही नेपाल को नया जीवन दे पाएंगे। सुशीला कार्की की जित भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाने के साथ भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की भी है। नेपाल में अभी जितने भी राजनीतिक रूल हैं, उसके सारे बड़े नेताओं के हाथ भ्रष्टाचार से सने हैं, चुनौती है राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करना भी बड़ी चुनौती है। राजधानी काठमांडू जिससे काष्टमंडप भी कहा जाता था, अब स्वाहा हो चुका है। मात्र 48 घंटे की अराजकता में अब स्वाहा बर्बाद हो गया। सरकार और विपक्ष भाग खड़े हुए। भ्रष्टाचार को अपनी जान बचाने को इधर-उधर भागना पड़ा। उन्हे घर के पिछवाड़े, नदी नालों के कद कर भागते हुए देखा गया। आंदोलनकारियों के पैरों में जो आए उनकी जमकर कुटाई हुई। युवाओं में सरकार हो या विपक्ष सभी नेताओं के प्रति ऐसा गुस्सा था कि चाहे संसद भवन हो या राष्ट्राध्यक्ष कार्यालय, सिंह दरबार हो या रेब्यू भवन सभी में आग लगा दी गई। सारे जरूरी दस्तावेज



जल्दकर स्वाहा हो गए। जेलों से भारी संख्या में कैदी फरार हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, दर्जनों मंत्रियों के आवास फूंक दिए गए। भारत नेपाल संबंधों को नया आयाम देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा नेपाल का गांधी भी कहा जाता है, स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला की प्रतिमा पर वीरगज में बरस रही हथौड़ा चलाते दृष्टा देखा गया। इधर जेन जी समूह में इस बात को लेकर वैचारिक मतभेद भी था कि अंतरिम सरकार को नेतृत्व धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का हो या राज संस्था विचारधारा का? सुशीला कार्की की शिक्षा वागणसी के बीएचयू में भी हुई है और यह भारत के प्रधानमंत्री को फालो करती हैं। जेन जी समूह के 40 प्रतिशत से अधिक कर्मी हैं। जेन जी पहली पदवी थीं। जेन जी का यह सही फैसला था कि उन्होंने एक साहसी न्यायविद महिला को अंतरिम सरकार का मुखिया चुना। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला न्यायाधीश थीं, अब पहली महिला प्रधानमंत्री का खिताब भी उनके खाते में दर्ज हुआ। राजशाही के जमाने से ही नेपाल का भारत से उतार-चढ़ाव जैसा संबंध रहा है। लोकतंत्र के भारती के बाद ज्यादातर नेपाली सरकारें भारत से मतलब भर का संबंध रखती थी। अभी अभी तत्कालपलट के शिकार हुए ओली की शिनाख्त कट्टर भारत विरोधी की रही है। उन्होंने नेपाल की जनता में भारत के खिलाफ जहर घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ा। सत्ता से हटने के बाद भी सेना के कैप्टन कपुर्न से उन्होंने तत्कालपलट के लिए मनागढ़त कर्तवियों के साथ भारत पर आरोप मढ़ा है। भारत नेपाल के बीच असमहमियाँ हैं, इसे लेकर प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का क्या रुख होता है, यह भी गौरतलब होगा। सनातनी विचारधारा से लैस पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की के हाथ नई सरकार की कमान भारत के लिए सुखद संकेत है। इस बात की कामना की जानी चाहिए कि सुशीला कार्की को नेतृत्व में नेपाल में लोकतंत्र मजबूत हो और वह फिर से उठा खड़ा होने में सक्षम हो।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

नेपाली युवाओं के आक्रोश का असर

का दोषी ठहराया। हमी नेपाल संगठन के लीडर व सामाजिक कार्यकर्ता सुन्द गुरुंग ने सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ युवाओं को एकजुट कर आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सोशल मीडिया प्रतिबंध का मुद्दा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और अक्षम शासन के खिलाफ लड़ाई है। इससे युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा क्योंकि ओली सरकार पर भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। और विगत वर्षों में सड़क निर्माण और बिजली परियोजनाओं में अरबों का घोटाला सामने आ चुका है। साथ ही युवा वर्ग पहले से ही शासन वर्ग के परिवारों को ठेके और नौकरियों व प्राथमिकता देने से नाराज था।

इसके साथ ही 2024 में आली सरकार द्वारा दो बार उपचुनाव बजलेन से राजनीतिक अस्थिरता बढ़ा और सत्ता परिवर्तन न जलना का विश्वास तोड़ा। रैपर से मेयर बन बालेन शाह ने फंसवुक पर जेन - जी के नेतृत्व में शुरू हुअ आंदोलन को सफल नहीं किया। बालेन, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के कारण नेपाल के युवाओं में बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। आर्थिक असमानता और बेरोजगारी के कारण नेपाल के युवा क्रस्त हैं, उनके अर्थव्यवस्था के गुस्से को नाल मिला। नेपाल की अर्थव्यवस्था मंदी से ग्रस्त है। नेपाल की अर्थव्यवस्था पर्यटन और रেমिटेंस अर्थात प्रवासी नेपाली मजदूरों से आना बाला धन, पर निर्भर है, यह व्यवस्था पटरी पर नहीं लौटी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों और उपप्लान बड़ा है, लेकिन युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं,

जबकि नेताओं के परिवार लगातार अमीर हो रहे हैं।
 बुनियादी ढांचे में निवेश कम है। जरूरतें—जो को लागू
 किए बिना विकास को माँहल टूट चुका है, इस विचार ने विविध
 प्रदर्शनों में ईंधन का काम किया। इसके साथ ही हिंदू
 धर्म और राजशाही समर्थक समाजवाद भी एक कारक
 बनकर लोगों को लगा कि हमारी समाज और सांस्कृतिक
 पहचान खोती जा रही है। इन कारणों ने एक ज्वालामुखी
 का रूप धारण कर प्रदर्शनों को हिंसक बनाया जिससे 19
 वर्षों की मृत्यु हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हैं, संसद
 भवन, प्रधानमंत्री आवास और अन्य सरकार संपत्तियों में
 आग लगा दी गई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को
 त्यागपत्र देना पड़ा। विद्रोह को रोकना समय की मांग है।
 सरकार यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन संकेत
 मिलते हैं कि सरकार के लिए हमें सार्थक उपाय करने होंगे ताकि
 वर्तमान संकट को शांत करके भविष्य का मार्ग प्रशस्त
 किया जा सके। इस हद तक रहकर लोगों से सेंना को
 राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखाकर अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक
 को आमंत्रित कर संवाद शुरू करना चाहिए। सोशल
 मीडिया पर प्रतिबंध हटा लिया गया है लेकिन एक न्यूज
 पर नियंत्रण के लिए पारदर्शी नीति बनाने जैसी जाएं
 और लोगों को बेरोजगारी को आर्थिक सहन देने हेतु बेरोजगारी
 भत्ता देने की व्यवस्था हो। पर्यटन को पुनर्जीवित किया
 जाए तथा विविध बैंक से आपाकालीन फंड मांगे जाएं,
 ताकि नेपाल की अर्थव्यवस्था और निर्माण को पटरी पर
 लाया जा सके।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

ओजोन परत के बिना असंभव पृथ्वी पर सुरक्षित जीवन का अस्तित्व

1 6 सितम्बर 1987 को मॉन्ट्रियल में ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, जिसमें उन रासायनों के प्रयोग को रोकने से संबंधित एक बृहद महत्वपूर्ण समझौता किया गया था, जो ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदाई माने जाते हैं। ओजोन परत को रोकने है, यह किन्तु तेजी से कम हो रही है और इस कमी को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसी संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए 1994 से प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है किन्तु निम्ना की बात यह है कि पिछले कई वर्षों से ओजोन दिवस मनाए जाते रहने के बावजूद ओजोन परत की मोटाई कम हो रही है।

प्रतिपाद एक विशिष्य थीम के साथ यह महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। विश्व ओजोन दिवस 2025 को थीम विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक है, जिस से संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है। यह थीम ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल के 40 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ओजोन परत के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विज्ञान की भूमिका और आवश्यक वैश्विक सहयोग पर केंद्रित है। विश्व ओजोन दिवस हमें स्मरण कराता है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत आवश्यक है और यह धरातल पर नियंत्रण प्रक्रिया की पीढ़ियों के लिए इसे बचाने हेतु निरंतर जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। आईपीसीसी की एक रिपोर्ट में तापमान में 1.5°C से अधिक बढ़ने के लिए 2030 तक 43% तक कोटेशन के लिए आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। आईपीसीसी की एक रिपोर्ट में तापमान में 1.5°C से अधिक बढ़ने के लिए 2030 तक 43% तक कोटेशन के लिए आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। आईपीसीसी की एक रिपोर्ट में तापमान में 1.5°C से अधिक बढ़ने के लिए 2030 तक 43% तक कोटेशन के लिए आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

विश्व ओजोन दिवस पर विशेष

युनिआपार के देशों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के रूप लक्ष्य निर्धारित करने की अपेक्षा को कम कर रही है। जहां तक भारत की बात है तो भारत ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को तीव्रता में 35 प्रतिशत की दर से घटाने का लक्ष्य रखा है किन्तु जी-20 देशों पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों की समीक्षा पर आधारित एक रिपोर्ट में कुछ समय पहले कहा गया था कि भारत सहित जी-20 देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वे तापमान वृद्धि को डेढ़ डिग्री तक सीमित करने के दृष्टिगत पर्याप्त नहीं हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल अखति परमाणु हासिल करने के लिए इन देशों को अपने उत्सर्जन को आधा करना पड़ेगा। रिपोर्ट में इस बात पर भी चिंता व्यक्त की गई थी कि पिछले जू-20 देशों की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो गई हो रही है, जहां अभी भी कोयले की 82 फीसदी जीवाश्म ईंधन ही इस्तेमाल हो रहा है और चिंताजनक रूप से जीवाश्म ईंधन की कुछ देशों में जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति पर सस्बिडी भी दी जा रही है। भारत ने हरित ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 2027 तक 47 फीसदी बना दिया है और 2030 तक सी फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन का भी लक्ष्य है। हालांकि नवीन ऊर्जा के इन लक्ष्यों के अतिरिक्त रिपोर्ट में भारत की सहजता भी की गई थी। विश्वभर के अधिकांश क्षेत्रों में आज जलवायु परिवर्तन के चलते विविधता का जो दौर देखा जा रहा है, उसके लिए काफी

हद तक ओजोन परत की कमी मुख्य रूप से जिम्मेदार है और हमें अब यह भी भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि हमारी लापरवाही और पर्यावरण से बड़े पैमाने पर खिलवाड़ ही पर्यावरण विनाश की सबसे बड़ी जड़ है। कुछ समय पूर्व एक रिपोर्ट में कहा गया था कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से चलते दुनियाभर में करीब 12 करोड़ लोग विस्थापित होंगे। ओजोन परत के सुखित न होने से मनुष्यों, पशुओं और यहां तक की वनस्पतियों के जीवन पर भी बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। यही नहीं, अंधकृश वैज्ञानिकों का मानना है कि ओजोन परत के बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और पानी के नीचे का जीवन भी नहीं बचेगा।

हिन्दी अकादमी दिल्ली के सौजन्य से पर्यावरण छपी चर्चित पुस्तक प्रदूषण मुक्त सांसें के मुताबिक ओजोन परत की कमी से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता सर्दियां अनियमित रूप से आती हैं, हिमखंड गल



शुरू हो जाते हैं और सदी की तुलना में गर्मी अधिक पड़ती है, पर्यावरण का यही हाल पिछले कुछ वर्षों से हम देख और भुगत भी रहे हैं। दरअसल ओजोन परत में कमी और मोटे पतले जा रहे छिद्र के कारण पृथ्वी तट पहुँचने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे स्वास्थ्य तथा पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत हानिकारक प्रभाव डालती हैं। ओजोन परत की कमी से हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। ओजोन परत वातावरण में बनती है जब सूर्य से पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन परमाणुओं को तोड़ती है और ए परमाणु जो ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं तो ओजोन अणु बनते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से 20-30 किमी की ऊँचाई पर वायुमण्डल के समतप मंडल क्षेत्र में ओजोन गैस का एक झोंका सा आवरण है। यह परत पर्यावरण की रक्षक मानी गई है क्योंकि यही वह परत है, जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। हमारे ऊपर के वातावरण में विभिन्न परतें शामिल हैं, जिनमें एक परत स्ट्रेटोस्फियर है, जिसे



ओजोन परत भी कहा जाता है। ओजोन गैस प्राकृतिक रूप से बनती है। निकले वातावरण में पृथ्वी के निकटतम ओजोन की उपस्थिति प्रदूषण बढ़ाने वाली और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक लेकिन ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत की उपस्थिति पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यावश्यक है। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन से टकराती हैं तो उच्च ऊर्जा विकिरण के कारण इसका कुछ हिस्सा ओजोन में परिवर्तित हो जाता है।

ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के लिए एक अच्छे फिल्टर के रूप में कार्य करती है। सूर्य विकिरण के साथ आने वाली पराबैंगनी किरणों का लगभग 99 फीसदी भाग ओजोन मंडल द्वारा सोख लिया जाता है, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी एवं वनस्पति सूर्य के तेज ताप और विकिरण से सुरक्षित हैं और इसी कारण ओजोन परत को सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। यही कारण है कि प्रायः कहा जाता है कि ओजोन परत के बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही संभव हो जाएगा।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

इजरायल के खिलाफ एकजुट हुए 50 मुस्लिम देश

ईरान ने कहा: इस्लामी देश इजरायल से रिश्ता तोड़ें, पाकिस्तान की नाटो जैसी फोर्स बनाने की सलाह

दोहा। कतर की राजधानी दोहा में आज मुस्लिम देशों के 50 नेता इजरायल के खिलाफ एक खास बैठक के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह बैठक अरब लीग और आगनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोआप. रेशन (ओआईसी) ने बुलाई है। इसका मकसद 9 सितम्बर को कतर पर हुए इजरायली हमले का जवाब देना है। इस हमले में हमस के 5 मंबर और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारा गया था।

यह हमला उन समय हुआ जब हमस की एक टीम गाजा में दो साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव पर बात करने दोहा में थी। आज की मीटिंग से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने मुस्लिम देशों से इजरायल के साथ रिश्ते तोड़ने को कहा है। उन्होंने इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील की। वहीं पाकिस्तान ने सभी इस्लामी देशों को नाटो जैसे जाइंट फोर्स बनाने का सुझाव दिया। इस्लामिक कोआ. परेशन की इमरजेंसी बैठक के लिए 50 से ज्यादा इस्लामी देशों के नेता कतर पहुंचे। रविवार को इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों ने दोहा में इजरायल के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर बंद कमरे में एक बैठक की थी। इस दौरान कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद



इजरायली हवाई हमले में यमन के 26 मीडियाकर्मी मारे गए: हूती

समूह सना। यमन की राजधानी सना में इजरायल के हवाई हमले में मारे गए 46 लोगों में से 26 लोग स्थानीय मीडिया संस्थान के कर्मचारी थे। यमन के हूती समूह ने रविवार को इसकी जानकारी दी। एक बयान में हूती समूह ने कहा कि हमले में मध्य सना में तहरीर चौक पर स्थित दो समाचार पत्रों- 26 सितम्बर और अल-येमन के कार्यालय ध्वस्त हो गए। उन्होंने कहा कि इस हमले से उनका मीडिया संचालन कमजोर नहीं होगा। हूती नियंत्रित स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि हमले में 165 लोग घायल हुए जिनमें महिला और बच्चे शामिल हैं। हूती द्वारा संचालित अल-मसरी टीवी ने क्षतिग्रस्त आवासीय इमारत और मलबे में खोजबीन कर रहे बचावकर्मियों का फुटज जारी किया। इजरायली सेना ने कहा कि उसने सैन्य शिविरों, हूतियों के जनसंपर्क मुख्यालय और एक इंधन भंडारण स्थल को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने साथ ही कहा कि ये कार्रवाई हूती समूह द्वारा किये गए ड्रोन और मिसाइल हमले के जवाब में थी। हूती के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने इस हमले का जवाब देने की कसम खाई।

बिन अब्दुलरहमान बिन जासिर अल थानी ने इजरायली हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि कतर अपनी संभूता

मुस्लिम इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने एक जाइंट डिफेंस फोर्स बनाने की संभावना का जिक्र किया और कहा कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान इस्लामिक समुदाय (उम्माह) के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएगा।

इजरायल ने 9 सितम्बर कतर की राजधानी दोहा में हमस चीफ खलील अल-हय्या को निशाना बनाकर हमला किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमले में अल-हय्या बच गया, जबकि 6 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी कहा था कि इजरायल इस हमले को 'पुरी जिम्मेदारी' लेता है। जब यह हमला तब हुआ जब हमस नेता अमेरिका के युद्धविराम प्रस्ताव पर आपस में चर्चा कर रहे थे। हमले के बाद कतर ने इजरायल की कड़ी आलोचना की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने इसे हमस के राजनीतिक मुख्यालय पर 'कायाना हमला' करार दिया था और कहा था कि यह सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। दूसरी ओर, इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने इस कार्रवाई की तारीफ की थी। उन्होंने कहा थी कि आतंकवादियों को दुनिया में कहीं भी इजरायल से छूट नहीं मिलेगी।



स्पेन। अललपार्डो से मैड्रिड तक ला वुल्टा साइकिल रेस के इक्कीसवें चरण के दौरान फलस्तीनी झंडे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर नारे लगाते लोग।

दोहा पर इजरायली हमले के बाद कैदियों की अदला-बदली पर बातचीत स्थगित

गाजा। हमस ने कहा है कि कतर की राजधानी दोहा में पिछले सप्ताह वार्ता के लिए गई उसके प्रतिनिधिमंडल पर इजरायली हमले के बाद कैदियों की अदला बदली के लिए इजरायल के साथ बातचीत निलंबित कर दी है। हमस के एक वरिष्ठ अधिकारी ताहिर अल-नोनो ने एक बयान में कहा कि अगर बातचीत के लिए जिम्मेदार प्रतिनिधिमंडल पर देश के अंदर हमला होता है, तो बातचीत जारी नहीं रह सकती। हमस ने कहा कि पिछले मंगलवार को इजराइली हवाई हमलों में दोहा

में उनके नेताओं द्वारा इस्तेमाल किए गए आवासीय परिसरों को तब निशाना बनाया गया, जब वे अमे. रिका समर्थित युद्धविराम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। समूह ने कहा कि वरिष्ठ हमस अधिकारी खलील अल-हय्या के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल बच गया। लेकिन हमस के पांच सदस्य और कतर का एक सुरक्षा अधिकारी मारे गए। अल-नोनो ने इजरा. इली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर युद्धविराम और कैदियों की अदला-बदली, दोनों के प्रयासों में बाधा डालने का आरोप लगाया है।

संक्षिप्त समाचार

सम्मेलन में बिम्स्टेक देशों के 80 युवा नेता शामिल हुए

नई दिल्ली। असम के गुवाहाटी में आयोजित तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन में बिम्स्टेक देशों के 80 से अधिक युवा नेताओं ने शिरकत की। गत नौ से 11 सितम्बर तक आयोजित बिम्स्टेक युवा नेता शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक को और मजबूत करने के लिए छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषित 21-सूत्रीय कार्य योजना का हिस्सा था। शिखर सम्मेलन में 21 वीं सदी के नेतृत्व पर प्रकाश डाला गया-लचीला, समावेशी और निविधता के प्रति संवेदनशील। उद्यमिता, डिजिटल थिंकिंग और अंतर-सांस्कृतिक सहयोग पर सत्रों ने प्रतिभागियों को स्थाई, सामाजिक रूप से उत्तरोत्तर समाधान तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया।

चीन, थाईलैंड संयुक्त वायु सेना प्रशिक्षण करेंगे

बीजिंग। चीन और थाईलैंड इस महीने के अंत में संयुक्त वायु सेना प्रशिक्षण आयोजित करेंगे। चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय (एमएनडी) ने सोमवार को जानकारी दी कि ये प्रशिक्षण थाईलैंड में आयोजित होगा। एमएनडी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, चीन इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए कई प्रकार के विमान और जमीनी वायु रक्षा बलों को तैनात करेगा।

इस्लामाबाद में डेंगू के 25 नए मामले मिले

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पिछले 24 घंटों में डेंगू बुखार के 25 नए मामले सामने आए हैं। जिला स्वास्थ्य कार्यालय (डीएचओ) के अनुसार नए संक्रमणों में से 13 ग्रामीण इलाकों में और 12 शहरी इलाकों में दर्ज किए गए, जिससे इस वर्ष राजधानी में डेंगू से पीड़ित लोगों की कुल संख्या 460 हो गयी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस समय कम से कम 21 मरीज शहर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं।

कांगो इबोला वायरस का टीकाकरण शुरू किया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि मध्य कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) में बुलापे स्वास्थ्य क्षेत्र में इबोला वायरस का टीकाकरण शुरू हो गया है। इस महीने की शुरुआत में कसाई प्रांत में इबोला वायरस का संक्रमण शुरू हुआ था। डब्ल्यूएचओ ने एक बयान में कहा कि इस चरण में अग्रिम पॉकेट के स्वास्थ्य कर्मियों और इबोला वायरस संक्रमण के पुष्ट मरीजों का टीकाकरण किया जा रहा है।

जेन-जैड ने सुशीला कार्की का इस्तीफा मांगा

कहा: हमने कुर्सी पर बैठाया, हटाने में वक्त नहीं लगेगा, बिना सलाह के मंत्री चुनने का आरोप

काठमांडू। नेपाल में जेन-जैड-प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम पीएम सुशीला कार्की का इस्तीफा मांगा है। वे कैबिनेट विस्तार को लेकर नाराज हैं। प्रदर्शनकारियों ने रविवार रात पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतरिम सरकार प्रदर्शनकारियों की राय लिए बिना मंत्रियों को चुन रही है।

इसका नेतृत्व सुदान गुरुंग कर रहे थे। गुरुंग ने धमकी देते हुए कहा, अगर हम फिर सड़क पर उतरे तो कोई हमें रोक नहीं पाएगा। जिस कुर्सी पर बैठाया है, वहीं से निकाल फेंकेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सोनियर वकील ओमप्रकाश आर्यल सरकार में दखलअंदजी कर रहे हैं। गुरुंग का आरोप है कि आर्यल ने खुद को गृहमंत्री बनाने का फैसला किया है। ओमप्रकाश आर्यल काठमांडू के मेयर बालेन शाह के करीबी माने जाते हैं। पीएम कार्की ने ओमप्रकाश आर्यल को गृह और कानून मंत्री, रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्री और कुलमान घिसिंग को ऊर्जा मंत्री नियुक्त



इसका नेतृत्व सुदान गुरुंग कर रहे थे, गुरुंग ने धमकी देते हुए कहा, अगर हम फिर सड़क पर उतरे, तो कोई हमें रोक नहीं पाएगा

किया है। कार्की ने तीन दिन पहले 12 सितम्बर को अंतरिम पीएम की शपथ ली थी। इस दौरान गुरुंग ने माथा टेकते हुए कार्की के पैर छुए थे। कार्की ने तीन दिन पहले 12 सितम्बर को अंतरिम पीएम की शपथ ली थी। इस दौरान गुरुंग ने माथा टेकते हुए कार्की के पैर छुए थे। 36 साल के गुरुंग ने 8 सितम्बर को काठमांडू में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। वे हामी नेपाल नाम के एनजीओ के संस्थापक हैं।

भारतीय मूल के नागरिक का सिर काटने पर भड़के ट्रम्प

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय मूल के चंद्र नागमलैया की हत्या की निंदा की। उन्होंने इसे भयानक बताया। ट्रम्प ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा चंद्र नागमल्लैया डलास के रहने वाले थे। उनकी पत्नी और बेटे के सामने, क्यूबा के अवैध अप्रवासी ने बेरहमी से उनका सिर कलम कर दिया।

हमारे देश में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। ट्रम्प ने बताया कि हमलावर को पहले भी बाल यौन शोषण, कार चोरी जैसे अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बाइडन प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि बाइडन प्रशासन ने इस अपराधी को रिहा कर दिया था और क्यूबा ने उसे वापस लेने से भी इन्कार कर दिया था। दरअसल, टेक्सास के डलास में 10 सितम्बर को भारतीय मूल के नागमलैया की हत्या कर दी गई थी। ट्रम्प ने कहा कि अवैध अप्रवासी अपराधियों के

बेलारूस पड़ोसी देशों को बिना मांगी सहायता नहीं देना चाहता: लुकाशेंको

मिन्सक। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने सोमवार को कहा कि बेलारूस अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। लुकाशेंको ने कहा कि उसके पास अपने पड़ोसियों की बिना मांगे सहायता करने की कोई योजना नहीं है। लुकाशेंको ने रूस की रजबेवचिक समाचार पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि बेलारूस बिना आमंत्रण के अपने पड़ोसियों की सोमवार पार करने की कोई योजना नहीं बना रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बेलारूस उन सभी के साथ मित्रता और सहयोग करने के लिए तैयार है जो ईमानदारी से ऐसा चाहते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि बेलारूस के प्रति पश्चिम की अभिन्न नीति आक्रामक होती जा रही है, लेकिन अभी तक उसे कोई विशेष जोखिम या प्रत्यक्ष सैन्य खतरा नहीं दिख रहा है।

अमेरिका-चीन के बीच टिकटॉक पर बनी सहमति

ट्रम्प ने दिए संकेत, कहा: अच्छी रही व्यापार वार्ता

टिकटॉक चीन से जुड़ी कंपनी है, जिसे अमेरिकी कानून के अनुसार बेचना होगा अन्यथा परिचालन बंद करना होगा

से बात करूंगा। यह रिश्ता बहुत मजबूत बना हुआ है। मैड्रिड में अमेरिका और चीन के अधिकारियों के बीच नई दौर की आर्थिक और व्यापारिक वार्ता चल रही है। अमेरिका की प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बसेंट और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीयर कर रहे हैं, जबकि चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप-प्रधानमंत्री है लियेंग कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और चीन के बीच संबंधों में कोई जटिलताएं हैं। व्यापार विवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं और तकनीकी उद्योग पर बढ़ते तनाव ने दोनों देशों के रिश्ते

को ठीक ठीक बना दिए हैं। इसके बावजूद, मैड्रिड की वार्ता को आने वाले समय में द्विपक्षीय रिश्तों के लिए अहम कदम माना जा रहा है। अमे. रिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने टिकटॉक की विक्री की समयसीमा कई बार बढ़ा चुके हैं। पहली बार ट्रम्प ने जनवरी को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद टिकटॉक पर अमेरिका में प्रतिबंध लगा दिया गया था। दूसरी बार अप्रैल में समयसीमा बढ़ाई गई, जब टिकटॉक को अमेरिकी कंपनी में बदलने को कोशिश हो रही थी, लेकिन ट्रम्प



पाक राष्ट्रपति ने चीन में जे-10 फाइटर जेट फैक्ट्री देखी

आसिफ अली जरदारी ने हथियारों की तारीफ की, भारत के खिलाफ संघर्ष में इनका हुआ था इस्तेमाल

बीजिंग। 10 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने चेंगदू स्थित चीन के एविएशन इंडस्ट्री काम्प्लेक्स का दौरा किया। पाकिस्तानी अखबार द डान के मुताबिक जरदारी इस जगह का दौरा करने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं। इस मौके पर उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी और बेटी असीफा भुट्टो-जरदारी भी मौजूद थे।

जरदारी ने कंपनी के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों से मुलाकात की और चीन निर्मित विमानों की क्षमताओं की सराहना की। इस दौरान जरदारी ने काम्प्लेक्स में जे-10 और जेएफ-17 थंडर विमानों के बनने की प्रक्रिया को समझा। इसके अलावा उन्होंने प्रचुर पीढ़ी के जे-20 स्टील्थ लड़ाकू विमान के बारे में भी जानकारी ली। जरदारी ने कहा कि जे-10 और जेएफ-17 ने



जरदारी ने कंपनी के इंजीनियरों व वैज्ञानिकों से मुलाकात की

पाकिस्तानी वायु सेना को मजबूत किया है और भारत के खिलाफ ये विमान पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान और चीन रक्षा उत्पादन और विमानन में सहयोग का विस्तार

करना जारी रखेंगे। पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी ने एविएशन इंडस्ट्री काम्प्लेक्स में विमानों के बनने की प्रक्रिया को समझा। जरदारी ने चीन की हाई-स्पीड ट्रेन का भी अनुभव लिया। वह चेंगदू से मियांथांग तक आधे घंटे की ट्रेन यात्रा पर गए। यात्रा के दौरान उन्होंने चीन की ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तारीफ की। उन्होंने पाल्पुशन भी इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन और भूकंप पूर्व चेतावनी तकनीकों को 'रेलवे इंजीनियरिंग का चमत्कार' बताया। चीनी अधिकारियों ने जरदारी को बताया कि चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई-स्पीड रेल नेटवर्क है, जिसकी लंबाई 45,000 किलोमीटर से ज्यादा है। यहां ट्रेनें 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और हर साल दो अरब से ज्यादा यात्रियों को ले जाती हैं। यह नेटवर्क लगभग सभी बड़े चीनी शहरों को जोड़ता है।

कैमरून के बार में विस्फोट में एक की मौत, चार घायल

यांडे। कैमरून के एंगोफोन उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के एक बार में रविवार को हुए आईईडी विस्फोट में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। सुरक्षा सूत्रों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार यह विस्फोट क्षेत्र के बतिबो इलाके में हुआ। बम एक पुलिस स्टेशन के पास एक बार में लगाया गया था। एक क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों के एक समूह ने बार को निशाना बनाया क्योंकि पुलिसकर्मी अक्सर वहां जमा रहते हैं। हालांकि, विस्फोट के दौरान कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। सभी पीड़ित नागरिक थे जो दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता रहे थे। किसी भी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने इस हमले के लिए क्षेत्र में सक्रिय अलगाववादी लड़ाकों को जिम्मेदार ठहराया है। अलगाववादियों ने सोमवार को स्कूलों के फिर से खुलने और अक्टूबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को बाधित करने के लिए कैमरून के अंग्रेजी भाषी उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रों में एक महीने का लॉकडाउन शुरू किया।

यौन समस्याएं

यौन समस्याओं के विशेषज्ञ

पुराने से पुराने यौन रोग के मरीज एक बार अवश्य मिलें

डा. सम्राट

नशामुक्ति, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा तम्बाकू, प्रोक्सीवॉन केम्यूल अफीम, चरस, डोहे पोस्ट इंजेक्शन व अन्य नशा छुड़ाने का स्थायी ईलाज।

नावल्टी सिनेमा चौक

मुजफ्फरनगर (यू.पी.)

M-9412211108